

(c) what are the reactions of the Government to the above proposals?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b) There have been suggestions from various quarters for setting up a TV Centre and film studio at Bhopal or other location in M.P. and for production of documentary films in that State.

(c) A proposal to set up a TV centre at Bhopal was included in the Draft Sixth Plan proposals (1980-85). The implementation of the Scheme will, however, depend on the approval of the Plan, availability of resources and relative priorities.

The setting up of film studios concerns the State Government and the private sector. The Films Division has produced a number of documentary films on Madhya Pradesh, and two more are on its production programme.

कोटा, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन केन्द्र

2152. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर एकमात्र शहर है जहाँ दूरदर्शन केन्द्र है;

(ख) क्या कोटा, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में निकट भविष्य में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोटा में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को माइक्रोवेव

लिकों के माध्यम से दूरदर्शन के विस्तार संबंधी छठी "योजना" (1980-85) के प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल किया गया है । तथापि, इसका कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

निकट भविष्य में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिजली की कटौती के कारण प्रत्येक राज्य में श्रम-घंटों की हानि

2153. प्रो निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली की कटौती के परिणाम-स्वरूप पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में विभिन्न उद्योगों में श्रम-घंटों की हानि हुई है; और

(ख) देश में बिजली की कटौती से बचने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) प्रणाली में विद्युत की कमी है जो अलग-अलग राज्य में तथा अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न होती है । किसी विशेष समय पर कमी की मात्रा वास्तविक मांग तथा निवल उपलब्धता के बीच अन्तर के ऊपर निर्भर करती है । इस अन्तर को पूरा करने के लिए विद्युत कटौतियाँ तथा प्रतिबन्ध लागू किए जाते हैं । उत्पादन में हानि होने में सहायक विभिन्न पहलुओं में से विद्युत की कमी एक है । केबल तथा अलग से लोड शैडिंग के कारण श्रम-घंटों की हानि की सही-सही मात्रा बताना संभव नहीं है ।

(ख) लोड शीडिंग की घटनाओं को कम करने की दृष्टि से प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के अतिरिक्त, छुट्टी के दिनों और शिफ्टों को अलग-अलग करके तथा जहां तक संभव हो सकता है व्यस्तताकालीन भार को अव्यवस्तताकालीन समय में अंतरित करके, जहां तक व्यवहार्य हो सकता है भार वक्र को समान करके मांग का बेहतर प्रबंध करने के संबंध में भी कदम उठाए गए हैं। प्रणाली में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सम्मिलित करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सले 1 पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें

(2) संयुक्त सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता।

(3) उपस्कर क डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिष्ठित करने के कार्यक्रम शुरू करना।

(4) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना।

(5) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों की विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(6) निर्माधीन समस्त विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से मानीटरिंग करना।

(7) ताप विद्युत केन्द्रों के लिए इंजीनियरों और प्रचालकों को प्रशिक्षण देना जिसके लिए सोसाइटी का गठन किया गया है।

राजस्थान को कुकिंग गैस की कमी और एजेंसियों का आवंटन

2154. प्रो० निर्मलकुमारी शर्मावत : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुकिंग गैस की अत्यधिक कमी है ;

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य में किन जिलों में कुकिंग गैस एजेंसियां आवंटित किए जाने का विचार है ; और

(ग) इन एजेंसियों के आवंटन के संबंध में क्या कसौटी अपनायी गयी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। राजस्थान के बाजारों में खाना पकाने की गैस की कुछ पिछली बकाया सप्लाई की जाती है।